to ask his friend, Israel, to concede the demand of the Palestinians for a homeland? I would like to know whether this question will be taken up and if it is to be taken up, what will the hon. Minister say?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The Government's policy *vis-a-vis* West Asia is well-known and it is also known to the Government of United States of America. Our policy is based on certain principles and one of the principles is that those who have been uprooted from their hearths and homes should be allowed to go back and that they should have a homeland. I do not understand why *my* friend, Mr. Malaviya, is having misgivings.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: Because two hon. Members from your party have been critical of your stand.

Implementation of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

f369. SHRI SHRIKANT VERMA: t
SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ:
SHRI DEORAO PATIL:
SHRI BAPURAOJI MAROTRAOJI DESHMUKH:
SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to refer to the reply to Starred Question 122 given in the Rajya Sabha on 17th June, 1977 and state:

(a) what is the present position in regard to the implementation of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 in each State;

(b) what are the names of the States where the system still exists; and

(c) what steps Government have taken to abolish the system in these *States?*

fThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Shrikant Verma.

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई) : (क) से (ग) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया था कि वे बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, जो 25 अक्तूबर, 1975 से लागू हुआ, अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को यथा-आवश्यक अधिकार देने तथा उनके जिम्मे यथाआवश्यक कार्य लगाने, जिलो तथा उपमंडलों में सतर्कता समितियां गठित करने और किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिनियम के अधीन अपराधों की जांच करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान करने के लिए समुचित कार्यवाही करें लगभग ऐसी सभी राज्य सरकारों ने, जिन्होंने अपने यहां बंधित श्रमिकों के विद्यमान होने की सूचना दी थी, अधिनियम के अधीन संबंधित प्राधिकारियों को या तो अधिकार प्रदान कर दिए हैं या निर्देश जारी कर दिए है। कुछ ऐसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने भी, जिन्होने यह सूचित किया है कि उनके यहां कोई बंधित श्रम पद्धति नहीं हैं, अधिनियम के अधीन इस प्रकार की कार्यवाही तथा सतर्कता समीतियां गठित की हैं ।

अब तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारों तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने अपने यहां बंधित श्रम पद्धति विद्यमान होने की सूचना

दी है । 31 अक्तूबर, 1977 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में पता लगाए गए, मुक्त कराए गए तथा पुन : बसाए गए बन्धित श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है :

बन्धित श्रमिकों की कुल संख्या

(31-10-77 की स्थिति के अनुसार)

	पता लगाए गए	मुक्त कराए गए	पुन: बसाए गए
1. आन्ध्र प्रदेश	1,298	1,298	698
2. बिहार	2,562	2,301	613
3. गुजरात	42	42	42
4. कर्नाटक	64,040	64,040	4,668
5. उड़ीसा	614	313	303
6. मध्य प्रदेश	1,612	1,500	33
7. केरल	900	900	186
8. राजस्थान	6,000	5,580	2,496
9. तमिलनाडु . . .	2,882	2,882	2,363
10. उत्तर प्रदेश	19,242	19,242	12,805
11. मिजोरम . . .	3	3	. .
जोड़ :	99,195	98,101	24,207

मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों को सरकारी विभागीय परियोजनाओं में उपयुक्त रोजगार देकर, कृषि के लिए भूमि और मकानों के लिए स्थान आंवटित करके तथा दूध देने वाले पशुओं, भेड़ों, बढ़ई-गीरों के औजारों आदि की खरीद के लिए ऋण देकर पुनः बसाया जा रहा है । मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा व होस्टलों में निशुल्क रहने की सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है । कलक्टरों को कृषि के प्रयोजनों के लिए ऋण देने के अधिकार दिए गए हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस प्रकार के श्रमिकों को रियायती दर पर ऋण भी दिए हैं । कलेक्टरों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वे मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों को चालू योजनाओं तथा चालू कार्यक्रमों (इन कार्यक्रमों में भूमि संरक्षण, सिंचाई कार्य आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण कार्यक्रम भी शामिल हैं) के अन्तर्गत पुन. बसायें ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The State Governments and Union Territories were requested to take appropriate action under the bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 which came into force from October 25, 1975 to confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary to ensure that the provisions of the Act are properly carried out, to constitute Vigilance Committees in the Districts and Sub-Divisions and to confer powers of a Judicial Magistrate for the trial of offences under the Act on any Executive Magistrate. Nearly all the State Governments which have reported the existence of bonded labour have their conferred powers or issued necessary instructions to the concerned authorities under the Act. Some of the States and Union Territories which have reported non-existence of bonded labour system have also taken similar action and constituted Vigilance Committees under the Act.

The State Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh and the Union Territory of Mizoram have reported the existence of bonded labour system so far. The latest available information about the number of bonded labourers identified freed and rehabilitated as on October 31, 1977 in each State is as follows:—

Total number of banded labourers

(position as on 31-10-77)

	Identified	Freed	Rehabilitated
1. Andhra Pradesh	1,298	1.298	698
2. Bihar	2,562	2,301	613
3. Gujarat	42	42	42
4. Karnataka	64,040	64,040	4,668
5. Orissa	614	313	303
6. Madhya Pradesh	1,612	1,500	33
7. Kerala	900	900	186
8. Rajasthan	6,000	5,580	2,496
9. Tamil Nadu	2,882	2,882	2,363
10. Uttar Pradesh	19,242	19,242	12,805
11. Mizoram	3	3	5
TOTAL	99,195	98,101	24,212

t[ ] English translation.

Freed bonded labourers are being rehabilitated by providing them with suitable employment in Government Departmental projects allotment of agricultural lands, house sites, loans for purchase of milch animals, sheep, carpentry implements, provision of education and free hostel facilities to the children of the freed bonded labourers. Collectors have been authorised to issue loans for agricultural purposes. Loans have also been given by the Nationalised Banks at preferential rates of interest to such labourers. Collectors have also been directed to re-habilitate freed bonded labourers under the on-going schemes and programmes including those of soil conservation, irrigation works, tribal and harijan welfare programmes.]

श्री श्रीकान्त वर्मा : सभापति महोदय, 26 नवम्बर, को श्रम मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया था कि बंधुआ मजदूरों के संबंध में जो कानून बनाया गया उस पर विभिन्न राज्यों में ठीक से अमल नहीं हो रहा है और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यवाही की जानी चाहिए । उसके बाद जो यह वक्तव्य दिया गया यह बिल्कुल हीला-हवाला है । और ऐसा लगता है कि केवल दिखाने के लिए दिया गया है । इसमें कोई ठोस बात नहीं कही गयी है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बंधुआ मजदूरों के सही आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश की है, क्योंकि 99195 की जो संख्या उन्होंने दी है तो इतने तो केवल मध्य प्रदेश में ही होंगे । और यह आंकड़े बंधुआ मजदूरों के बिल्कुल गलत हैं और झूठे हैं । तो मेरा पहला सवाल यह है कि सही आंकड़े इकट्ठा करने के लिए उनकी सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री लारंग सई : श्रीमन् जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है हम राज्यों की सरकारों पर निर्भर रहते हैं और उनसे जो आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं वहां के आंकडे हम ने यहां रखे हैं । जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ है और यह केवल हीला-हवाला है, मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं है । बंधुआ मजदूरों की प्रथा को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार भी प्रयत्नशील है और अभी राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था उसमें श्रम मंत्रीजी ने उनको फिर से कहा है कि आप अपने राज्यों में इस का और पता लगायें कि यदि कहीं पर भी इस तरह के मजदूर पाये जाते हैं तो उस प्रथा को समाप्त करने के लिए सख्ती के साथ कार्यवाही की जाय, ऐसा उन लोगों से निवेदन किया गया है ।

श्री श्रीकान्त वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी शायद नये हैं इसलिए मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता । श्रम मंत्री जी यहां मौजूद हैं और 99195 की जो संख्या यहां दी गयी है उसमें केवल 24207 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है । इसके बावजूद मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बड़ी भारी तादाद में पुनर्वास किया गया है । बड़े शर्म की बात है कि सरकार को सत्ता में आये 8 महीने हो गए और जो लोग 800 साल से गुलामी में रह रहे हैं उन के पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, उनके संबंध में वक्तव्य बाहर गोल मोल दिए जाते हैं और यहां भी एक मंत्री जी ने उठ कर कहा कि बहुत कुछ किया गया है । यह उन तमाम गरीब लोगों के साथ मखौल है । खुद मंत्री जी आदिवासी इलाके के रहने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर रहते हैं तो इस तरह से उनको जवाब नहीं देना चाहिए । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या भूमि सुधार किया जाएगा जिससे कि भूमि

सुधार के तमाम पहलुओं को सरकार ध्यान में रखेगी जसा कि खुद गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री ब्रह्मदत्त ने कहा है कि जब तक समस्त पहलुओं को दृष्टि में नहीं रखा जाता तब तक इनका हल नहीं। क्या मंत्री जी तमाम कलेक्टरों और आफिसरों के विरुद्ध दण्ड विधान करेंगे ?

श्री लारंग सई : श्रीमन्, पुनर्वास का प्रश्न बंधुआ मजदूरों के लिए एक बहुत ही नाजुक प्रश्न है । माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि इस प्रकार के बंधुआ मजदूर जिन इलाकों में ज्यादा संख्या में हैं, मैं वहीं का हूं। श्रीमन्, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनको केवल जमीन दे देने मात्र से ही उनके पुनर्वास का सारा काम नहीं हो जाएगा, इसमें कठिनाई है । श्रीमन्, बंधुआ मजदूरों के पास कोई ऐसी पूंजी नहीं रहती जिससे वह बैल खरीद सकें और जमीन खरीद सकें। केवल जमीन दे देने मात्र से उनका पुनर्वास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें कदम उठाती हैं, कार्य करती हैं। इसमें यह बात सही है कि हो सकता है कि जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उसमें कमी है । हम प्रयास कर रहे हैं कि काम ज्यादा तेजी से हो ।

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ: Will the hon. Minister say categorically what concrete steps are being taken to rehabilitate about 74,000 bonded labour which is not a small number?

श्री लारंग सई : श्रीमन्, बंधुआ मजदूरों को बसाने के लिए केन्द्र सरकार से जो निर्देश राज्य सरकारों को गया है, उसके अनुसार राज्य सरकारों ने भी निर्णय कर लिया है कि न केवल बंधुआ मजदूरो बल्कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं सब को भूमि दी जाए ।

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ: I want to know what concrete steps have been taken about bonded labour.

श्री लारंग सई : श्रीमन्, बौंडेड लेबर के संबंध में इनको प्राथमिकता दी गई है और कहा गया है कि सबसे पहले बंधुआ मजदूरों को बुला कर उनका पुनर्वास किया जाए । इस प्रकार के सख्त निर्देश राज्य सरकारों ने भी अपने अधिकारियों को दिये हैं ।

श्री देवराव पाटील : श्रीमन् इसमें जो (ग) में पूछा गया है, उसमें यह बताया गया है कि इन राज्यों में इस पद्धति को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये । उसका कोई जिक्र रिप्लाई में नहीं आया है। हर एक प्रान्त में जहां बौंडेड श्रमिकों की संख्या क्या है उसका जवाब गवर्नमेंट ने दिया है । उसके मताबिक —State-wise number of the bonded labour— is as follows:

उत्तर प्रदेश में 31 मई को जो फिगर दी है उसमें 31 हजार बंधुआ मजदूरों की संख्या दी गई है और 31 अक्टूबर को जो संख्या दी गई है उसमें 19 हजार दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि गलत पता लगाया है । सभापति जी, इस संबंध में जो एक्ट बना हुआ है उसके सेलियेन्ट फीचर्स में सिर्फ यह बात ही नहीं है कि उनके पुनर्वास के लिए कोई साइट दे दी जाय बल्कि उनको इकनोमिक सहायता कितनी दी जाय और उनको कितनी सोशियल फैसिलीटीज दी जायें, उसका भी साफ-साफ उल्लेख किया गया है।

MR. CHAIRMAN: Be brief.

श्री देवराव पाटील : Very brief, Sir. सभापति जी, प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इस बारे में क्या कर सकते हैं। जवाब में यह भी नहीं बताया गया है कि

इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेटों में कौन-सी मशीनरी है । इसके अलावा to provide for the economic and social rehabilitation of the freed bonded labour, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है । उन लोगों को कितने एडवान्स दिए गए, कितना उसका रिपेमेंट हुआ, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है । इसके अलावा बोंडेड कर्ज के बारे में उनको कोई कर्ज मिला या नहीं और इस बारे में कितने पैंडिंग मामले हैं, कितनी डिक्रियां हैं, इसका भी जिक्र नहीं किया गया है । यह भी नहीं बताया गया है कि कितने लेबरर्स की प्रोपर्टी को मनी-लेंडर्स द्वारा हथिया लिया गया है और कितनी प्रोपर्टी एटैच की गई है, इसका भी जिक्र नहीं किया गया है । I want all this information. That is the purpose for which I asked the question.

MR. CHAIRMAN: You can say straightway that all this information is not there. He will collect this information.

श्री देवराव पाटील : मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक्ट में जो प्रोविजन है और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो बात कही गई है उसके संबंध में कोई इनफारमेशन नहीं दी गई है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक दी जाएगी ? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन स्टेटों में बोन्डेड लेबर नहीं हैं उन स्टेटों के नाम क्या हैं ?

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, the hon. Member has a series of questions to ask. But we went by the question as was put to us, and that only said: "What steps Government have taken to abolish the system in these States?" But if the very long list of items that he has now introduced about accounts, payments, what has been done about realisation etc. were given in that question, it would have been possible for us to answer them. But, perhaps, then it might have been an Unstarred question and he would not have had the chance to ask his questions. But he has raised some other points and I would like, with your permission, to answer them. First of all, he knows, as well as others too...

श्री देवराव पाटील : सभापति जी, सवाल के (क) भाग में यह पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य में बंधक श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

SHRI RAVINDRA VARMA: वर्तमान स्थिति के बारे में तो एक एनसाइक्लोपीडिया प्रकाशित हो सकता है । सवाल में तो एनसाइक्लोपीडिया नहीं आ सकता है ।

Sir, as far as the question of bonded labour itself is concerned... *(Interruption)* ... The hon. Member should please listen to the answer as well, I can understand his impatience, but we are equally impatient to see that the system is abolished. He should have the patience to listen to the answer. He raised the question about the number of States in which we have no reports about the existence of bonded labour. Sir, to begin with, I would like to say, as my distinguished colleague said, that in this matter, we have to depend, to a large extent, on the State administrations. Sir, the States which have answered us and said that there is no bonded labour existing in their jurisdiction are—Meghalaya, Maharashtra—from which the hon. Member hails—Nagaland, Manipur, Tripura, Haryana, Pondicherry, Andaman-Nicobar Islands, Lakshdweep, Chandigarh, Delhi, Dadar and Nagar Haveli, These are the States. But. Sir, the States can also have second thoughts and, perhaps some of them may identify bonded labour.

On the other question that he raised, I can tell him that a number of steps have been taken in this regard. Over 16,000 accounts have been opened

—he asked about the accounts—in various banks lor rehabilitating bonded labourers and Rs. 2 crores have teen provided under various schemes formulated by the banks for their re-habilitation.

श्री देवराव पाटील : महोदय, यू०पी० को जो फिगर 19 हजार...

MR. CHAIRMAN: You have taken much more time than necessary.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: In those States where action has already been taken to implement the Act, this bonded labour being away from the public eye, especially in plantations, is the hon'ble Minister aware that there are starvation deaths? Therefore, may I know if the Govern-ment will constitute some investigating machinery to find out the plight of those areas where bonded labour have already severed their connections from their masters?

SHRI RAVINDRA VARMA: Wherever there is bonded labour this problem of identifying them becomes a major problem. Here, again, it is very necessary for us to secure the fullest co-operation of the administration at the lowest level as well as the voluntary organisations who are in a position to draw the attention of the existence of bonded labour either in a disguised form or in an overt form. About the question the hon'ble Member has raised as to what happens after identification and liberation is very important because in cases where the bonded labour has been identified but libera-tion has not taken place it is quite likely that such people are subjected to even greater indignities and difficulties. This is, therefore, a pressing problem and we are taking such steps as we can from here to ensure that the local administration takes such steps as are necessary to deal with the situation.

SHRI ABU ABRAHAM: May I know from the Minister why those who have been identified have not been freed in many States? What is the reason for not taking action to free them?

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, first, of all, I would like to say since the House is very much interested in this question that the major problem in this regard is not liberation after identification or their rehabilitation but the major problem is that of identification because of lack of information which enables us to spot them and then to liberate.

As far as this question of the difference in the numbers identified and the difference in the numbers liberated is concerned, when you identify a person who is under a system of bonded labour you can inform him of the fact that the law has set him free. But this information that the law has set him free and he is no longer in bondage is not adequate for him to act as a free agent because many times even after the information is received there is scepticism, there is inaction, there is unwillingness to face the consequence unless there is an economic assurance about his future. This is the reason why even when some bonded labourers who have been identified are informed of the fact that they are free and they are no longer in bondage there is some time lag between the two. In such cases we have repeatedly drawn the attention of the State Government to the fact that the administrative machinery has a role to play. As the hon'ble House is aware, even section 372 of the I.P.C. makes it a punishable offence to hold any one in bonded labour. Therefore, we have advised them in all such cases to launch penal action where bonded labour has been identified but not liberated. At the moment I do not have the figures of the number of cases where such actions have been taken.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन् क्यों उत्तर प्रदेश का माला आया है, इस लिये मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मनी लैंडिंग का कानून बना दिया है कि बिना लाईसेंस

के कोई मनी लैंडिंग नहीं कर सकता । मनी लैंडिंग के अंतर्गत ही बंधक-लेबर सिस्टम चलता था अब उत्तर प्रदेश में कोई भी बोंडेड-लेबर नहीं है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो 19 हजार की फिगर उन्होंने दी है, उसके बारे में क्या वे एक सेम्पल सर्वे करायेंगे कि वह फिगर सही है या गलत है ? मैं यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फिगर गलत है ।

SHRI RAVINDRA VARMA: Mr. Chairman, Sir...

SHRI K. K. MADHAVAN: Mr. Chairman. Sir. I should like to know ....

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. Are you a new Member? The Minister is replying.

SHRI RAVINDRA VARMA: We share the hon'ble Member's scepticism about the figures that have been given by us. There must be an adequate survey in this regard.

SHRI G. LAKSHMANAN: Sir, is the hon. Minister aware that a new system of bonded labour has come into exist ence for the past so many years? The previous Government did not take any action but I hope the present Government will take some action. The Kabuliwallahs or Pathans are doing money lending business in the whole of India without licence—they are thousands in number—and they are making bonded labourers of the Central Government, State Government and public sector employees. So, what action does this Government propose to take?

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, in all cases where, as the law has defined "bonded labour", we can identify bonded labour, action will be taken.

MR. CHAIRMAN: Question Hour Is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Opening of a passport office in Bangalore

*362. SHRI MULKA GOVINDA REDDY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state-

(a) what is the number of applica tions received from Karnataka for the issue of passports after the liberalisation of rules regarding issue of pass ports; and

(b.) whether there is any proposal under Government's consideration to open a passport office in Bangalore for the convenience of the applicants from. Karnataka?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Between 15 August 1977 and 15 November 1977, 6,512 applications for passports have been received from the State of Karnataka.

(b) The criterion for opening a pass port office in a State is that atleast 30,000 applications must be received from it in a year. The number of pass, port applications received from Kar nataka for the period 1 January 1977 to 15 November 1977 was 18,546. Gov ernment is keeping a continuous watch, on the level of passport applications received from each State.

Murder attempt on an Indian official in Kustlalumpur

*363. SHRI JANARDHANA REDDY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Hindustan Times of the 10th November, 1977 to the effect that an armed robber recently broke into the house of an official of the-Indian High Commission in Kualalumpur and shot him in the arm and stomach;

(b) if so, what are the details of the incident; and